

पहले से ही ट्रेनों में भीड़, कन्फर्म टिकट तक मुरिकल अब 7 ट्रेनों निरस्त की, 24 का रूट बदला, यात्रियों की परेशानी और बढ़ी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

रेल यात्रियों की परेशानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब 7 ट्रेनों को निरस्त करने और 24 का रूट बदलने से यह परेशानी और बढ़ गई है। जबकि पहले से ही ट्रेनों में भीड़ चल रही है कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। रेलवे ने इस बार दावा किया है कि उत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के बाराबंकी-अयोध्या-शाहगंज-जफराबाद रेल खण्ड के दोहरीकरण काम के तहत बाराबंकी स्टेशन पर यार्ड रिमाइंडलिंग किया जाना है इसलिए 12 दिसंबर से 05 जनवरी तक प्री-नान इंटरलॉक एवं 06 से 15 जनवरी तक नान इंटरलॉक किया जाना है जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है।



इन ट्रेनों के रूट बदले

1- गोरखपुर से 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 एवं 31 दिसंबर तथा 04, 05, 07, 11, 12 एवं 14 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12511 गोरखपुर-कोट्टौली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

2- कोचूवेली से 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 एवं 31 दिसंबर तथा 02, 03, 07, 09 एवं 10 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12512 कोचूवेली-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।

3- बारौनी से 18 एवं 25 दिसंबर तथा 01 एवं 08 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12521 बारौनी-एनार्कुलम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

4- एनार्कुलम से 15, 22 एवं 29 दिसंबर तथा 05 एवं 12 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12522 एनार्कुलम-बारौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।

5- गोरखपुर से 13, 20 एवं 27 दिसंबर तथा 03 एवं 10 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12589 गोरखपुर-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

6- सिकन्दराबाद से 14, 21 एवं 28 दिसंबर तथा 04 एवं 11 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12590 सिकन्दराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।



7- गोरखपुर से 16, 23 एवं 30 दिसंबर तथा 06 एवं 13 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12591 गोरखपुर-शावन्तपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

8- यशवन्तपुर से 11, 18 एवं 25 दिसंबर तथा 01 एवं 08 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 12592 यशवन्तपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।

9- गोरखपुर से 19 एवं 26 दिसंबर तथा 02 एवं 09 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15023 गोरखपुर-यशवन्तपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

10- यशवन्तपुर से 14, 21 एवं 28 दिसंबर तथा 04 एवं 11 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15024 यशवन्तपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।

11- गोरखपुर से 14, 21 एवं 28 दिसंबर तथा 04 एवं 11 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15029 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

12- पुणे से 16, 23 एवं 30 दिसंबर तथा 06 एवं 13 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15030 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेण्ट्रल-प्रयागराज ज़.-सुल्तानपुर-अयोध्या कैप्टन-अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी।

13- गोरखपुर से 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 एवं 31 दिसंबर तथा 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14 एवं 15 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बस्ती-मनकापुर-अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

14- गोरखपुर से 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 एवं 31 दिसंबर तथा 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14 एवं 15 जनवरी को चलने वाली गाड़ी संख्या 15066 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बस्ती-मनकापुर-अयोध्या-अयोध्या कैप्टन-सुल्तानपुर-प्रयागराज ज़.-कानपुर सेण्ट्रल के रास्ते चलाई जाएगी।

इस बार ईवीएम से होंगे भोपाल अभिभाषक संघ के चुनाव

8 जनवरी को मतदान, आज नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

उपाध्यक्ष पद पर 4 सचिव पद पर 2 नामांकन फार्म पहुंचे हैं। 12 दिसंबर को नामांकन भरने की आधिकारी तिथि है। चुनाव ईवीएम से कराने से समय और धनराशि की भारी बचत होगी। ईवीएम का डेमो भी सम्बावना को ढांचे का बायोलैप्रैवर्टिंग किया गया। चुनाव समिति ने निर्णय लिया है की उम्मीदवार की वरिष्ठता स्टेट बार कार्यसिल के पंजीयन से निर्णयित की जाएगी।

12 जनवरी को नई कार्यकारिणी होगी तैयार

20 और 21 दिसंबर को नामांकन फार्म वापसी के बाद 22 दिसंबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 4 एवं 5 जनवरी को टैंडर वोटिंग होगी। 8 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। 9 और 10 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम प्रोत्साहित किया जाएगा। 12 जनवरी को नई कार्यकारिणी का कार्यालय ग्रहण होगा।

बीयू में 18 दिसंबर से तृतीय सेमेस्टर के साथ होंगी पूरक परीक्षाएं



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा एमए, एमकॉम और एमएससी के तृतीय सेमेस्टर के साथ पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं 18 और 19 दिसंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेंगी।

जानकारी के अनुसार, एमए तृतीय सेमेस्टर, एमए हिस्ट्री तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 26 दिसंबर तक होगी। वहाँ

एमए व एमएससी न्यू मैट्रेसेटक्स एवं पूरक परीक्षा 18 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी तक चलेंगी। इसी तरह एमएससी तृतीय सेमेस्टर के तहत होम साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, फुट न्यूट्रिशन, एमकॉम तृतीय सेमेस्टर और मून डिपार्टमेंट के पेपर 19 से 27 दिसंबर तक, जबकि एमएससी तृतीय सेमेस्टर के पेपर 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे।

मेट्रो एंकर

संत नगर में हुई अशासकीय शिक्षण संस्था संगठन की अहम बैठक

पदाधिकारी बोले - एमपी बोर्ड से पांचवीं बोर्ड परीक्षा निरस्त करने की करेंगे मांग

हिंदूराम नगर, दोपहर मेट्रो।

जिला अधिभाषक संघ के 8 जनवरी को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर भूतपूर्वी न्यायालय में तैयारियां चल रही हैं और प्रत्याशियों और मतदाताओं में सरगमी तेज हो रही है। कार्यक्रम जारी होने के साथ ही भावी प्रत्याशी जोर-शेर से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रविंद्र तवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा होना शुरू हो गए हैं। फहले दिन अध्यक्ष पद पर 8,



मंडल, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जे.डी.महोदय से प्रबंधवार के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। संस्था के सचिव बसंत चेलानी ने कहा कि कई वर्षों से विद्यालय को ऋक्षशी फीस का पूर्व के वर्षों की फीस का भी भुगतान नहीं किया गया है। प्रबंधवार के माध्यम से शिक्षा विभाग को पिछले वर्षों एवं 2022-23 की ऋक्षशी का भुगतान हो जाएगा। बैठक दो बजे से जल्द करने हेतु अवगत करायावाया जाएगा। संस्था के संरक्षण विभाग द्वारा गोपनीय विद्यालय विभ



शब्द ही खुशी शब्द ही गम,
शब्द ही परेशनी शब्द ही सुलझान।'

- अज्ञात

I am kind;

अब नयी शुरूआत का वक्त

S

प्रीम कोर्ट के एक फैसले ने जम्मू-कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा समाप्त किए जाने से जुड़े विवाद पर अब पूर्ण विवाह लगा दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 370 पर आया यह फैसला निर्विवाद रूप से युगांतरकारी कहा जा सकता है।

फैसले ने तीन बातें शीर्ष की तरह साफ कर दी हैं। पहली यह कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरी, जम्मू-कश्मीर को किसी भी रूप में अंतरिक संप्रभुता हासिल नहीं थी। तीसरी बात यह कि इस विशेष प्रावधान को समाप्त करने के पीछे किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। यह यूरोपी प्रक्रिया वैध और सर्वेधानिक है। इन तीनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस विवाद को आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश रह गई है और न ही जरूरत। जहां तक जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्रसासित क्षेत्र घोषित किए जाने की बात थी, तो इससे केंद्र-राज्य संबंधों के कई जटिल पहलू भी जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को खुला रखा है, लेकिन सालिंसिर जनरल की बात को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्वाख के केंद्रसासित क्षेत्र बने रहने में कोई बाधा नहीं है फैसले का एक अहम हिस्सा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि अगले साल सितंबर तक हर हाल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवा लिए जाएं। चूंकि जम्मू-कश्मीर अन्य क्षेत्रों की तरह देश का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार और सभी सर्वेधानिक संस्थानों का दायित्व है कि आम देशवासियों की तरह वहां के नागरिकों के भी सभी संवेधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार कायम रहें। जब ऐतिहासिक विवादों और बहसों से सेटल किया जा रहा हो तब वह चात खुलाई नहीं जा सकती कि जम्मू-कश्मीर इस मायने में भी खास रहा है कि वहां के लोगों को आतंकवाद और अलगाववाद के प्रभावों के लिये तरह की तरफ तक लंबे समय तक झेलनी पड़ी है। दाईं दशक में इसकी कीमत कश्मीर को हर तीके से चुकाना पड़ी है। वहां की जनता अपने 2 अधिकारों व बेहतर जीवन जीने की चाह को मजबूत तक पर रखी हुई दिखाये हैं। दहशत ने सामाजिक व आर्थिक ढांचे को भी बरबाद ही किया है। इस लिहाज से जिस्टिस एसके कौल के जजमेंट में की गई यह सिफारिश बहद अहम है कि स्टेट और नॉन स्टेट प्लेयर्स की तरफ से 1980 के बाद से वहां हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक पुराने और जटिल विवाद को पीछे छोड़ते हुए जम्मू-कश्मीर को और वहां के लोगों को साथ ले कर आगे बढ़ने की एक मजबूत जरूरी तैयारी की है। अब उमीदी की जाना चाहिये कि सभी पक्ष इस मैके का बेहतर इस्तेमाल करेंगे और देश के इस बहुत दूर तक रहने के प्रयास करेंगे। अगले नौ महीने के भीतर जब कश्मीर में चुनाव होंगे तो यह राज्य के निवासियों के लिये मौका होगा कि वह अपनी सरकार चुनें और अपना विकास तथा भविष्य का रास्ता प्रशस्त करें। कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को भी पुरानी हठ और तल्खी छोड़कर आगे आना चाहिये और स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिये। अब यही उन्नित है कि कल भी जीती सारी बातों को भुलाकर नयी सुबह और नये नजारे को देखा जाए।

चुनाव के टंग बदल रहे हैं, अब अंतिम दौर की कवायद पर टिका सब कुछ

चुनाव अब केवल दोनों पक्षों के भाषणों, नीतियों या घोषणा-पत्रों की लड़ाई नहीं रह गए हैं। अंतिम समय के अभियानों, बूथ प्रबंधन और उदासीन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने की क्षमता से ही आज चुनाव जीते या हारे जा रहे हैं।

पी. चिंदंबरम

नव चाहे कोई भी हो, लेकिन खासकर राज्य विधानसभा चुनावों के बाद शोर-शोरा होता ही है। जिन्हें जीत मिली, वे जेन मनते हैं और हारने वाले राजनीतिक दलों के समर्पक आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। लेकिन चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद जो शांति दिख रही है, वह सामान्य नहीं है। अगर यह प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के परिपक व्यवहार का प्रमाण है तो हम इसका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वजह कांग्रेस की उदासीनता है तो यह चिंता का विषय है। चलिए, शुरूआत करते हैं मेरे एक गलत अनुमान से। मैंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, लेकिन मैं गलत था। कांग्रेस की 35 की तुलना में 54 सीटों के साथ भाजपा को वहां प्रभावी अंतर के साथ जीत मिली। कांग्रेस शुरूआत से ही राज्य पर दावा कर रही थी, जिसे सभी सर्वेधानिकों में माना भी जा रहा था। कई लोगों से बतायी तके आधार पर मैं भी इससे सहमत था। लेकिन नतीजों ने भाजपा को छोड़ सभी को हैट में डाल दिया। यह पता चला कि सामान्य, एससी और एसटी सीटों पर कांग्रेस के बाट शेरों में भी आपने सहमत थी। 2018 में जीती एसटी की सभी सीटों गंवाने के साथ ही कांग्रेस ने अपनी हार की लिख लिख दी। हालांकि आपको याद होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के संबंध में कांग्रेस के दावों को मैंने स्वीकार नहीं किया था।

राजस्थान में गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया था, लेकिन सत्ता विरोधी लहर उनके गले की फांस बन गई। नतीजा यह रहा कि गहलोत सरकार के 17 मंत्री और कांग्रेस के 63 विधायकों को चुनावों में मुंह की खानी पड़ी। इससे मरियों और विधायकों को लेकर जनता की भारी नाराजी का संकेत मिलता है। जाहिर है कि चुनावी सर्वे जनता की नाराजी के स्तर को भांप नहीं सकते। अखिलकार, 1998 के बाद से राजस्थान के मतदाताओं की कांग्रेस और भाजपा में अदला-बदली करने की आतंत जारी रही। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय विफलताओं और भ्रष्टाचार के आधारों के बीच शिवराज की राजनीतिक विहारी लालों बहन जैसी कई योजनाएं लाल कीं। जिनका पायदा उठने तक रहने वाली थी। यह राज्य हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी थी। आरएसएस और इसके सहयोगी संगठनों ने एक सक्रियता के साथ जनता में गहरी जड़ें जारी रखी थीं।

भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश से उड़ाड़ने के लिए संगठन की तरफ से सरकार प्रयासों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर वैसा कुछ नहीं किया। जबकि भाजपा ने राज्य में केंद्रीय मरियों, मौजूदा सांसदों सहित कदम नेताओं का जमावड़ा एकत्र किया। समय व संसाधनों के भारी निवेश ने तेलंगाना में जरूर मैंने भी आरएसएस सरकार के खिलाफ एक

ग्रामीण लहर को महसूस किया था और किंवि चमक्का के होने की संभावना भी जाहिर की थी। के चंद्रेशेखर राव को पृथक तेलंगाना राज्य हासिल करने और वहां राज्य बंधु जैसी लाभकारी योजनाएं सहमत करने के बाद राजस्थान के मतदाताओं को लेकर जनता की भारी नाराजी का संकेत मिलता है। जाहिर है कि चुनावी सर्वे जनता की नाराजी के स्तर को भांप नहीं सकते। अखिलकार, 1998 के बाद से राजस्थान के अचारों, हैदराबाद के केंद्रित विकास, मुख्यमंत्री की खुद को अलग-थलग रखने वाली शिक्ष्यता और चरम बेरोजगारी ने सरकार के खिलाफ एक लहर पैदा की, जिस पर सवार रेत रेड्डे ने एक आक्रामक अभियान चलाया और कांग्रेस की जीत दिलाई।

अंतर कम रहा-तीन हानि हिंदी भाषी राज्यों में हार मिलने के बावजूद कांग्रेस को वोट शेर बरकरार रहा। आंकड़े खुद ही बोलते हैं। अंतीम बात यह है कि द्विश्वाय प्रतिस्पद्धी राजनीति अभी जिंदा है। कांग्रेस का वोट शेर चारों राज्यों में 40 फौसदी यानी कीरीब 2018 जितना ही रहा, जो चारों लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी ओर, भाजपा को चारों राज्यों में वोट शेर में बढ़त मिलता और उन्ने चारों राज्यान्यायों और शरीरी क्षेत्रों की ज्यादातर सीटें जीत लीं। मध्य प्रदेश को छोड़ कर बाकी जगहों पर वोट शेर में अंतर काफी कम है। छत्तीसगढ़ में 4.04 फौसदी का अंतर आदिवासी वोटों के शिफ्ट होने की वजह से दुड़ा। यहां अनुसन्धित जनजातियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में

से 17 भाजपा और 11 कांग्रेस ने जीती। राजस्थान में 2.16 फौसदी का अंतर तो और पीक मथा।

चुनाव बदल गए हैं-वोट शेर में जो अंतर रहे, उन्हें समझने के लिए चुनावों की बदलती प्रकृति को समझना जरूरी है। चुनाव अब केवल दोनों पक्षों के भाषणों, तैलियों, नीतियों या घोषणा-पत्रों की लड़ाई नहीं रह गए हैं। इन सभी का महत्व है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। अंतिम समय के अभियानों, बूथ प्रबंधन और उदासीन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने की क्षमता से ही आज चुनाव जीते या हारे रहे हैं। इसके लिए है।

निर्वाचन क्षेत्र में समय, ऊजाँ और पैसे के भाषणों के साथ किया जाता है। 2024 के लोकसभा आयोग की बात यह है कि चुनाव विवादों के बावजूद भाजपा को वोट शेर चारों राज्यों में आपने ग्रामीण राज्यों में जीता। यह अपने ग्रामीण राज्यों में जीता है। यह सभी के लिए अच्छा है। यह भाजपा को आपने लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी ओर, भाजपा को चारों राज्यों में वोट शेर में बढ़त मिलता और उन्ने चारों राज्यान्यायों और शरीरी क्षेत्रों की ज्यादातर सीटें जीत लीं। मध्य प्रदेश को छोड़ कर बाकी जगहों पर वोट शेर में अंतर काफी कम है। छत्तीसगढ़ में 4.04 फौसदी का अंतर आदिवासी वोटों के लिए आरक्षित 29 सीटों में

केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले: सीईओ

नर्मदापुरम, दोपहर मेट्रो

विकसित भारत संकल्प यात्रा

केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिवर्तित कराने के लिए प्रदेश के साथ ही नर्मदापुरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरारी और केंद्रीय योजनाओं से वित्तीय हितग्राहियों को लाभान्वित करवायेगी। जिले के समस्त विभागों की यात्रा में अहम भूमिका रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसएस रावत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज कलेक्टोर कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये और बीड़ियों कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमों से चर्चा कर यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशों के अनुसुरुप कार्यक्रम का व्यवस्थित संचालन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन-कल्याण की प्रमुख योजनाओं का लाभ लालोंगों तक पहुंचायें के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2024 तक 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अयोजित की जा रही।

उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंचायें के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2024 तक 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अयोजित की जा रही।

उन्होंने कहा कि यात्रा के लिये 7 प्रचार वाहन जिले में आयेंगे, जिसमें बड़े वाहन नगरीय क्षेत्र के लिये तथा छोटे वाहन ग्रामीण



क्षेत्र में भ्रमण कर भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी के बीड़ियों सदेश के माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमों से चर्चा कर यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशों के अनुसुरुप कार्यक्रम का व्यवस्थित संचालन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन-कल्याण की प्रमुख योजनाओं का लाभ लालोंगों तक पहुंचायें के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2024 तक 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अयोजित की जा रही।

क्षेत्र में भ्रमण कर भारत सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार करें। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी के बीड़ियों सदेश के प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी के बीड़ियों सदेश के विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम खलों पर स्वास्थ्य शिविर लागाए जाएंगे। इनमें सामाजिक स्वास्थ्य यात्रा जाँच की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। यात्रा के दौरान आयोजित शिविर स्थान पर प्रधानमंत्री ऊँचवाला योजना के विहारियों के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे साथ ही ऐसे दिक्षान, पश्च यात्राकारी, मछुआरे, जिलाकार पास झेड़िट कार्ड नहीं हैं, उनके आवेदन लेने और संबंधित बैंकों से समन्वय कर कोडिंग कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्र में आयार कार्ड के अपेक्षण का कार्य और विभिन्न योजनाओं को लाभाधिकारी लाभाधिकारी का नामांकन एवं चयन होगा।

क्षेत्र में भ्रमण कर भारत सरकार की योजनाओं में योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना है। सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच बनाना जो किहाँ कारणों से इन योजनाओं का लाभ लेने से विचित्र रह गये हैं। केन्द्र की योजनाओं के संबंध में जानकारी का प्राप्त करना एवं नायारिकों से योजनाओं के संबंध उनके अनुभव जानना है। योजनाओं की गतिविधियों जिले के जिन्हें जनजातीय गौवं दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायतों स्तर पर भी जन-जागरूकता की गतिविधियों संचालित की जायेगी जिसमें जागरूकता, सामुदायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा सूचना-सिक्षा-संचार वेन, आईटी प्लेटफॉर्म, और मोबाइल एलाइकेशन भी उपयोग में लाये जायेंगे। जिला, ग्राम पांचायत और स्थानीय शासन की समिति और केन्द्र सरकार के संगठन और संस्थाओं से प्लानिंग, समन्वय और निगरानी की जायेगी।

ग्रामीण इलाकों के लिये प्रमुख योजनाओं में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयल अल्योदय योजना, प्रधानमंत्री ऊँचवाला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री इंवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों इंडिया, उडान, बड़े भारत ट्रेन, अनुत भारत स्टेन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में प्राप्त दिवारियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जायेगा। जिले के शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन से प्रचार प्रसार किया जायेगा। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा नियमित नोडल अधिकारी और विरुद्ध अधिकारियों की समिति बनाई गई है। जिसमें केंद्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी।

सीईओ रावत ने बताया कि जिला संचालन भी उपरांत विकास के कल्याण के लिये स्थानीय विभागों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयल अल्योदय योजना, प्रधानमंत्री ऊँचवाला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री इंवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों इंडिया, उडान, बड़े भारत ट्रेन, अनुत भारत स्टेन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में प्राप्त दिवारियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जायेगा। जिले के शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन से प्रचार प्रसार किया जायेगा। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा नियमित नोडल अधिकारी और विरुद्ध अधिकारियों की समिति बनाई गई है। जिसमें केंद्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी।

सीईओ रावत ने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में विरुद्ध अधिकारियों की एक समिति तथा ब्लॉक स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। जिला स्तर पर भारत सरकार के संगठनों-संस्थाओं से दो प्रतिनिधियों को शामिल रहेंगे। आईटी पोर्टल डेटा को अंतिम रूप दिया जायेगा। वन का अबांटन, रस्ते योजना, वेन का कार्यक्रम स्थल, जागरूकता के लिए जिले में प्रचार योजना तैयार करना, वेन का नोडल अधिकारी बनाना ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विभाग-वार वर्क्षीय और शहरी नियमित विभागों में नामांकन के समय देश की सहायता को उपलब्ध कराएंगे।

सीईओ रावत ने बताया कि जिला संचालन भी उपरांत विकास के कल्याण के लिये स्थानीय विभागों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयल अल्योदय योजना, प्रधानमंत्री ऊँचवाला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री इंवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों इंडिया, उडान, बड़े भारत ट्रेन, अनुत भारत स्टेन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में प्राप्त दिवारियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जायेगा। जिले के शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन से प्रचार प्रसार किया जायेगा। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा नियमित नोडल अधिकारी और विरुद्ध अधिकारियों की समिति बनाई गई है। जिसमें केंद्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी।

सीईओ रावत ने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में विरुद्ध अधिकारियों की एक समिति तथा ब्लॉक स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। जिला स्तर पर भारत सरकार के संगठनों-संस्थाओं से दो प्रतिनिधियों को शामिल रहेंगे। आईटी पोर्टल डेटा को अंतिम रूप दिया जायेगा। वन का अबांटन, रस्ते योजना, वेन का कार्यक्रम स्थल, जागरूकता के लिए जिले में प्रचार योजना तैयार करना, वेन का नोडल अधिकारी बनाना ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विभाग-वार वर्क्षीय और शहरी नियमित विभागों में नामांकन के समय देश की सहायता को उपलब्ध कराएंगे।

सीईओ रावत ने बताया कि जिला संचालन भी उपरांत विकास के कल्याण के लिये स्थानीय विभागों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयल अल्योदय योजना, प्रधानमंत्री ऊँचवाला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री इंवेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों इंडिया, उडान, बड़े भारत ट्रेन, अनुत भारत स्टेन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में प्राप्त दिवारियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जायेगा। जिले के शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन से प्रचार प्रसार किया जायेगा। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा नियमित नोडल अधिकारी और विरुद्ध अधिकारियों की समिति बनाई गई है। जिसमें केंद्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से सम

